

# शाह टाइम्स

बोली, मंगलवार 14 अप्रैल 2026 बोली संस्करण: वर्ष 23 अंक 133 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें: **सुपन पढ़ें E-paper**

shahtimes2015@gmail.com

बैसाख कृपा पक्ष 12 विक्रमी सम्वत् 2083

25 शबाल 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुम्बई, देहरादून, इटावा, मुदाबाद, बोली, मेरठ व सत्रजक से प्रकाशित



**परिसीमन, महिला आरक्षण को लेकर सोनिया गांधी ने सरकार पर साधा निशाना** पृष्ठ 2



**आईपीएल 2026: बेहतरीन प्रदर्शन से परफ लैफ केप पर प्रसिद्ध कृष्णा का कब्जा** खेल टाइम्स



**आखिर सुनी गई आधी आबादी की आवाज** सम्यादक्रीय



**ब्रिटेन होर्मुज् स्ट्रेट की नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा: स्टामर** पृष्ठ 12

## खाड़ी से ओमान तक कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा अमेरिका के ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के ऐलान की धमकी पर ईरान ने किया पलटवार

**तेहरान, बार्त**

ईरान- अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने सख्त चेतावनी दी। ईरान को सेना ने कहा है कि अगर उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया, तो निरपराध लोगों को संकोर आमोन सागर तक कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

अमेरिका ने साफ किया है कि वह तब समय से ईरान के सभी बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाजों की रोकने की कार्रवाई शुरू करेगा। यह फैसला उस

**तेल की कीमतों में आठ प्रतिशत की वृद्धि**

मार्को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की होम्ज् स्ट्रेट की नाकेबंदी की घोषणा के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में आठ प्रतिशत का उछाल आया और ब्रेट क्रूड 102 डॉलर प्रति बैरेल के पर पहुँच गया। ब्रुन का ब्रेट क्रूड बायबद रिजर्वर (मालदीव समानुसार संयोजन तक 3:31) तक फिले बंद पाप से 7.76 प्रतिशत बढ़कर 102.59 डॉलर प्रति बैरेल पर आकर कर रहा था, जबकि मई का डब्ल्यूओएल- बायबद 8-2 प्रतिसरत बढ़कर 104.51 डॉलर पर पहुँच गया।

अमेरिका के खतम हो गई। अमेरिका का इस अंतराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बयाना

और कहा कि ये तो समुद्री डकैती के बराबर है। ईरान को सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ कहा है कि समुद्री सुरक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के बंदरगाहों को खतरा हुआ, तो पूरे क्षेत्र में किसी भी देश का बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि किसी भी सैन्य जहाज के खिलाफ कहीं कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका सेंट्रल कमांड के अनुसार यह नाकेबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। जो ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या वहाँ से बाहर निकलेंगे। हालाँकि गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच जाने वाले जहाजों को होम्ज् स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

## भारत सरकार ने हर स्तर पर सहयोग किया: फयाली

**नई दिल्ली।** पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे दुनिया को चिंता बसा दिया है। दुसरी ओर पाकिस्तान में हुई शक्ति बार्त के असरकाल के के बाव हालात और गंभीर हो गए हैं।

इसी बीच भारत में ईरान के राजदूत महुमद फयाली ने एक साथ सभी पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इनके साथ ही ईरान के रिजर्व मंत्रालय और भारत के आयातित हैं, जो संकेत के समर्थ और वे सार्वभौमिकता के समर्थ हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के तत्काल से होम्ज् स्ट्रेट में नाकेबंदी के ऐलान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी।

**ईरानी राजदूत ने भारतीयों का जताया आभार**

इस दौरान फयाली ने भारत सरकार का भी धन्यवाद कहा। इस संकेत के समर्थ में भारत सरकार ने जल्दी सभी व्यवस्थाएँ करने में मदद की। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर सहयोग किया। विदेशी हालात को देखते हुए भारत के रिजर्व मंत्रालय और भारत के आयातित हैं, जो संकेत के समर्थ और वे सार्वभौमिकता के समर्थ हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के तत्काल से होम्ज् स्ट्रेट में नाकेबंदी के ऐलान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी।

### संक्षिप्त समाचार

**खुदरा महंगाई दर मार्च में बढ़कर 3.40 प्रतिशत पर पहुँची**

नई दिल्ली। खुदरा मूल्यसूचकांक मार्च में मासुली रूप से बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.21 प्रतिशत थी। सरकार ने संकेत दिया कि इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों के आधार पर, मार्च में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की दर 3.87 प्रतिशत रही, जो पिछले माह के 3.47 प्रतिशत से अधिक है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई सूचकांक क्रमशः 3.63 प्रतिशत और 3.11 प्रतिशत रहेंगे। हालाँकि, यह मासुली उच्चतर लक्ष्यक सिद्ध होकर नई है, क्योंकि सामान्य मूल्य वृद्धि अभी भी 4 प्रतिशत से अधिक है।

सूचकांक और प्रदर्शन सूचकांक से नीचे नीचे हुई है। आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि शहरों की इलाका प्रशासनिक बजट हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 3.63 प्रतिशत बढ़े की गई, जबकि कृषि मूल्य सूचकांक शहरी इलाकों में यह दर 3.11 प्रतिशत के निचले स्तर पर रही। यह अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गाँवों और शहरों के बीच मूल्य दबाव किस प्रकार भिन्न है। फरवरी बजट में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली खाद्य बजटों की कीमतों में हल्का इजाजत देखा गया है।

**ट्रम्प की चेतावनी के बीच भारत पहुँचे ईरानी क्रूड के जहाज**

नई दिल्ली। अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच एक बड़ा खबर सामने आई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी जारी है और इसी दौरान लगभग सात साल के लंबे अंतराल के बाद ईरानी कच्चे तेल की खपत भारत पहुँची है। अमेरिका को और से वी प्रतिक्रिया में अस्थायी स्ट्रेट के चलते करीब 40 लाख (4 मिलियन) बैरेल कच्चा तेल लेकर दो सुपरटेकर भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पहुँचे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने अमेरिका-ईरान सशस्त्र बार्त विफल हो गई है और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी (ब्लॉकड) का ऐलान किया है।

ईरान-इजरायल युद्ध के अंतर्गत ईरानी फौजियों ने नाकबंदी बंद कर दिया। ईरान ने ईरान के तेल की खपत में लगभग 20 लाख (2 मिलियन) बैरेल कच्चा तेल है, जिसे मार्च के मध्य में ईरान के खार्ग द्वीप से लोड किया गया था।

## प. बंगाल में SIR से बाहर हुए लोग नहीं डाल पाएंगे वोट

**शाह टाइम्स ब्यूरो**

जब तक संबंधित अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक ऐसे व्यक्तियों को वोट देने की इजाजत कानून के खिलाफ होगी: सुप्रीम कोर्ट

**सुप्रीम कोर्ट फर्जी मतदान पर सख्त, केंद्र सरकार व चुनाव आयोग से मांगा जवाब**

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदान से पहले मतदाताओं की जांचेन्द्रिक और फंस रिकॉर्ड-नाम पहचान लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। यह याचिका मायायन वोट अतिरिक्त कृपार उपायगाने में परत की है। सीआईआई सुरक्षित और न्यायमूर्ति जयपालया बागवती को वोट ने मामले पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए निगमों में बतलाव की जरूरत होगी और इससे सरकार को खर्चाने पर बड़ा वित्तीय बोझ भी पड़ सकता है।

व्यक्तियों को वोट देने की इजाजत देना कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ होगा। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार जोषी ने कहा कि यह अंतराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बयाना

**लालू प्रसाद को 'जमीन के बदले नौकरी मामले' में निचली अदालत के सामने पेश होने से छूट**

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजदूत प्रयाल लालू प्रसाद को 'जमीन के बदले नौकरी' मामले को कार्यवाही में निचली अदालत में पेश होने से छूट दी है। न्यायालय श्री प्रयाल को उस याचिका पर सुनौती कर रही थी, जिसमें सीआईआई के मामले को सुनौती दी गई है। इसमें मुख्य प्राधिकारी से अनिवार्य पूर्व मंजूरी के बिना कतिपय तौर पर नई पुस्तक और जांच शुरू करने के केंद्र को भी सुनौती दी गई है। इससे पहले 24 मार्च को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीआईआई की याचिकाओं को रद्द करने से इन्कार कर दिया था। अदालत ने श्री याचक के उस तर्क को खारिज कर दिया था।

## मुजफ्फरनगर बनेगा नगर निगम सीएम योगी ने जनपद को दी 951 करोड़ की सौगात

**शाह टाइम्स ब्यूरो**

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगी योगी आदिजनपद में एक और बड़ा पहलूकाल पर तंत्र कया, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाने की बड़ी घोषणा कर पाकिस्तान की नई दिशा तय की।

मुजफ्फरनगी ने कहा कि आज पाकिस्तान आर्थिक बहालती से युद्ध रहा है और वहाँ के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में जो सुरक्षा और विकास का माहौल है, उसकी कल्पना भी पाकिस्तान में नहीं की जा सकती। उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करते हुए क्षेत्र के किसानों, युवाओं और महिलाओं को देश के लिए प्रेरणादायक बयाना। मुजफ्फरनगी में विपणन पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग प्रवेश की शक्ति और विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक अशांति फैलाने वाले ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने मुजफ्फरनगर के विकास के लिए 951 करोड़ रुपये की 423 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक अशांति फैलाने वाले ऐसे तत्वों से सावधान रहने की

**देश के इतिहास में 16, 17 और 18 अप्रैल महत्वपूर्ण: जयंत चौधरी**

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया एवं केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनताधिकार गठबंधन का सपना चौधरी चरणसिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1983 में देखा था और आने वाले समय में यह गठबंधन और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी में क्या विश्वास है, वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब भारतीय तंत्र के युवाओं को नौकरशाही दी जा रही है। उनका कि 2014 से पहले देश में स्टैंडअप पर कोई नीति नहीं थी। मुजफ्फरनगी योगी आदिजनपद किसानों के लिए सामान्य को सफल है। चौधरी ने कहा कि देश के इतिहास में 16, 17 और 18 अप्रैल महत्वपूर्ण तिथियाँ साबित होंगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले ऐतिहासिक कदम हैं।

को देश के लिए प्रेरणादायक बयाना। मुजफ्फरनगी में विपणन पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग प्रवेश की शक्ति और विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक अशांति फैलाने वाले ऐसे तत्वों से सावधान रहने की

### नोएडा हिंसा के बाद सख्त हुई योगी सरकार

**शाह टाइम्स ब्यूरो**

**मजदूर-उद्योग विवाद सुलझाने को बनी हाई लेवल कमेटी**

नोएडा। हिंसा के बाद योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मजदूरों और उद्योगों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में पहल की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदिजनपद के



मुजफ्फरनगर: वृद्ध रोजगार मेले में उम्र के सीएम योगी चर्चित उम्मीदवार को निवृत्ति पर सौंपते हुए। साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी व अन्य।

### विधायिका में महिलाओं को आरक्षण 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय: पीएम

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में पेश किए गए नारी शक्ति वंश अधिनियम को 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को सभी वर्गों में शक्ति और समर्थन से पारित किया, जो महिला सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण की जा रही है।

लेकटाइक बार्तों में आशा का आभारकता को पूरा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी ने इस संवैधानिक से पारित किया और निष्पक्ष ने खाली तौर पर 2029 तक महिला आरक्षण कानून लागू करने की जरूरत पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि लेकटाइक बार्तों में महिलाओं को आभारकता देने की आवश्यकता परतकों से महत्त्वपूर्ण की जाती रही है। उन्होंने कहा कि भारत की 'नारी शक्ति' 'देश के विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। नारी शक्ति वंश अधिनियम पीएम मोदी ने कहा कि वहाँ किसी को उपरोक्त देने का जिम्मेदार करने नहीं, बल्कि देश को महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया है।

## पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात

**एस्. आलम अंसारी**

**देहरादून।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंगलवार को अपने 28 वें वीर पर उत्तराखण्ड पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथे हुए सात के कार्यक्रम में यह उनका 18वां वीर होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान 11970 करोड़ की 210 किमी/घंटा लंबे दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना (एक्सप्रेस वे) के सात वीर, हिंदी में एक हजार मीगावट क्षमता वाले देश के पहले वैरिएटल स्पीड पंथ स्टेशन संबंध का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगमन को लेकर उत्तराखण्ड वारिसों में बवाल उरसा है। प्रदेश सरकार लोकार्पण समारोह को

**प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्तराखण्ड वारिसों में जबरदस्त लगभग 12, एक हजार क्षमता वाले देश के पहले वैरिएटल स्पीड पंथ स्टेशन संबंध का भी लोकार्पण करेंगे।**

**हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्यवासी करेगे पुष्प वर्षा टिटरों में लोकार्पण, एक हजार मीगावट क्षमता वाले देश के पहले वैरिएटल स्पीड पंथ स्टेशन संबंध का भी लोकार्पण करेंगे।**

**वेरिएटल स्पीड पंथ स्टेशन संबंध का भी लोकार्पण करेंगे।**

**पीएम मोदी के हृदय में बसता है उत्तराखण्ड: सीएम**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखण्ड से कम और माँ का रिश्ता नहीं है। उत्तराखण्ड उनके हृदय में बसता है। उनके वीरों को लेकर देवभूमि वारिसों में भारी उत्साह है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखण्ड में अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में मंजूरी मिली है। दो लाख करोड़ से अधिक की विकास योजनाएँ धरातल पर उतर चुकी हैं। मुजफ्फरनगी में राज्य के लिए इस अवसर को अत्यंत -शेष पृष्ठ दो पर करेंगे।

करीब 1000 मीगावट क्षमता के इस प्लांट का निर्माण टिटराद्वीपी 2400 मीगावट क्षमता के हिंदी हार्डवेयर पावर कालेजस -शेष पृष्ठ दो पर करेंगे।

क्षमता के इस प्लांट का निर्माण टिटराद्वीपी 2400 मीगावट क्षमता के हिंदी हार्डवेयर पावर कालेजस -शेष पृष्ठ दो पर करेंगे।













# लखनऊ के लिए बसपाई ट्रेन से रवाना

### वरिष्ठ नेता फिरोज आफताव व नरेश गौतम के नेतृत्व में रवानगी, सरफराज राईन भी होंगे शामिल

#### शाह टाइम्स ब्यूरो

सहारनपुर। बाबा साहब ड्रा. भीमराव अंबेडकर की जयंती की रीति पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिये हजारों की संख्या में बसपाई लखनऊ के लिये रवाना हुए।



सुन्दरलाल डायना, डा. बिन्दरपाल, गणेश हसन, जहोर कुरेशी, उरसान कुरोशी समेत सैकड़ों बसपाई शामिल रहे।

बसपा के मंडल कोर्डिनेटर हाजी सरफराज राईन नजीबाबाद से लखनऊ के लिये ट्रेन द्वारा रवाना हुए। वह नजीबाबाद में अपनी पत्नी की श्रादी में शामिल होने गये थे। जहां से वह शरादी के बीच से हो बहनजी के आहवाण पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिये लखनऊ के लिये रवाना हुए।

कल (आज) बाबा साहब ड्रा. भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर बसपा द्वारा लखनऊ के डा. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें शामिल होने के लिये बसपा मुख्य मंडल कोर्डिनेटर नरेश गौतम, वरिष्ठ नेता फिरोज आफताव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बसपाई लखनऊ के लिये रवाना हुए। नरेश गौतम ने कहा कि लखनऊ में आयोजित होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। लखनऊ जाने वाली में जिलाध्यक्ष रजनीश बंधु, पूर्व जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद, सुबुल प्रधान, सरवर प्रधान मण्डल संयोजक राजेश उजाला, आसिफ अली, सुरील जयसवाल, अजय सिंह, यशवीर धोबी, सुमित कर्णवाल,

## संवाद कर महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर

#### शाह टाइम्स ब्यूरो

सहारनपुर। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर प्रथममंती नरेंद्र मोदी ने संवाद करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।



निर्माण को मजबूत करेगी।

कार्यक्रम में महानगर प्रभारी वार्ड पी सिंह चवमन सिद्ध के साथ प्रदर मंत्री नूनन शर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री गुणा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वर्षा चौपड़ा, अनुसूचित जाति की क्षेत्रीय मंत्री मीनाका गंगवार, नगर उपाध्यक्ष कंचन धवन, नगर उपाध्यक्ष नीलू राणा, नगर मंत्री सोहन करण, नगर मंत्री आरती शर्मा, प्रदेशर महिला संघ की मंत्री अना आठवाल, उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी, असा सचिवलाल पुष्पा मालिक, मीमा, अनिता पक्खोत्रा व समस्त पदाधिकारी आदि मौजूद रही।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी और नेतृत्व में बढ़ि होगी। प्रथममंती ने जोर दिया कि नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और यह पहल विकासवादी भारत के

#### मारपीट का आरोप

चिलकाना। रघुनाथपुर छोटी पठेडु निवासी पीड़ित ने पो युवकों पर उसके साथ मारपीट कर धाकल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़ित रोहित कुमार पुत्र मंगेयन निवासी ग्राम रघुनाथपुर उर्फ छोटी पठेडु ने थाना पर तहरीर देकर बताया है कि विगत 10 अप्रैल को वह एक स्कूल से बच्चों को लेकर अपने घर जा रहा था। आरोप है कि जैसे ही वह पठेडु बाजार में पहुँचा वहाँ जाँक सवार वेश पुत्र रमेश तथा कमल पांडे से आगे ओ पीड़ित को गाली देने लगे। पीड़ित ने गाली देते की वजह पृच्छी तो उपरोक्त आरोपी दोनों भाईयों ने पीड़ित के साथ मारपीट शुरू कर दी।

## मेयर व विधायक दोनों भ्रष्ट: मनीष

#### शाह टाइम्स ब्यूरो

सहारनपुर। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनीष ल्याणी ने कहा कि मेयर व विधायक दोनों ही भ्रष्ट हैं।



मनीष ल्याणी ने यह बात हाउस अरेंजमेंट किये जाने पर कही। उन्होंने कहा कि वे हमार्यो कैसी आजादी है एक लोकतान्त्रिक एवं स्वतंत्र देश का नागरिक बिना किसी अपराध के उसे पुरे दिन उसी के घर में कैद किया हुआ है। कारण बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं हमें डर है कहीं आप मुख्यमंत्री से ना मिल लें। कोई मुझे बताया क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या मैं आतंकवादी हूँ आखिर मेरे मित्रने से किसके डर लग रहा है। मैं अगर शहर में हो रहे भ्रष्टाचार नगर की सड़क पर व्यापार करने वाले दुकानदारों का रोनाचो टप हो चुका है उसका जिम्मेदार शहर विधायक और महापौर हैं क्योंकि दोनों में डर बात को लड़ाई है की पिछले 3 सालों में 3 बार तोड़कर वार्ड जा चुकी है हकीकत नगर की सड़क पर व्यापार करने वाले दुकानदारों का रोनाचो टप हो चुका है उसका जिम्मेदार शहर विधायक और महापौर हैं क्योंकि दोनों में डर बात को लड़ाई है की

## बाबा साहब ने दिये समान अधिकार: रूही

#### शाह टाइम्स ब्यूरो

सहारनपुर। समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंबेडर ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में सबको समान अधिकार दिये हैं।



कहीं अनुभव आज जनमंच में आयोजित विचार गोष्ठी व रक्तदान शिविर को समर्थित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के वतारे मार्ग व आदर्शों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पार्षद व सपा के वरिष्ठ नेता अशोक टिंकु अरोड़ा ने बाबा साहब को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने पुरी दुनिया में इस देश को सबसे बेहतरीन संविधान दिया है। हमें उनके दिखाये मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज व देशहित में काम करना है। उन्होंने रूही अनुभव के साथ सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया।

## पेंथर्स व एवेंजर्स ने मैच जीते

#### शाह टाइम्स ब्यूरो

सहारनपुर। गली मोहल्ला कांपोर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए।



पहले मैच में बिबेन्स लीजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 243 रन बनाए। विल्लु ने 49 और अजयलाल ने 46 रन बनाए, जबकि तनु शर्मा ने 3 विकेट लिए। जबकि में सहायपुर पेंथर्स ने 17 ओवर में 244 रन बनाकर मुक. पारशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिलकाना क्षेत्र के गांव हाडाडाखेडी में लीग इंडियन क्रिकेट के टावर के सेल्टर कम से अंशतः दोरों में 42 लेल उमर कर 600 चोरी कर लिये।

गया। दूसरे मैच में स्टेड क्रै ऑफ इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन की पाठर खेली, जबकि कार्तिक शर्मा ने 54 रन बनाए। आभिर ने 2 और विष्णु कुमार ने 26 रन का योगदान दिया। एवेंजर्स की ओर से नवीन ने 4 और वीरेंद्र ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सहायपुर एवेंजर्स ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। सचिन वर्मा ने 39 और वायूष राणा ने 34 रन बनाए। आकाश और आशीष को 1-1 विकेट मिला। सचिन वर्मा तीन ओवर में शीव रहे। मैच के दौरान जयल इंद्रप्रोथ, राकेशा प्रस्थानी, शुभम बलवर्धन, मनीष, दीपक चौधरी, वरुण शर्मा, संभर, जावेद सलिल अन्य लोग मौजूद रहे। युपीएसए चौलंबर क्रीडा केंद्र सचयस साजिद उमर, सहायपुर टिचिस्ट्रिक्ट क्रिकेट परामर्शदाता से लीगक डर रहमान, डॉ. संजीव विद्यामानी, डॉ. उमकेश और डॉ. ऋषि पुडुवती भी उपस्थित रहे।

## बंजर भूमि पर जबरन निर्माण कार्य



नकडू। जनपद सहायपुर के एक गाँव में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा प्रस्तावित भूमि के बजाय अन्य में, की जबर भूमि पर सरकारी द्वारा आवंटित दुकान का निर्माण कार्य जबरन कराया जा रहा है।

अनुपन्ना दुकान का प्रस्ताव पारित करने की बात बताया गया था। जबकि ग्राम प्रधान व सचिव की दमर्हों के चलते कुर्छाई के लिए पूर्व से ग्रामीणों की आवंटित खसरा नं.180 की भूमि में अनुपन्ना दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है की प्रधान द्वारा जिस भूमि पर प्रस्ताव पारित किया गया था उसी जमीन पर दुकान बनाई जानी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों की भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ग्रामीण सुरेंद्र कुमार के अनुसार उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर जिलाधिकारी से लेकर 1076, एसडीएम, तहसीलदार, व तहसील दिवस तक पर शिकायत दर्ज कराई गई है। जबकि उनको शिकायतों के आधार पर गाँव में लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोकवाया दिया था। आरोप है कि उसके बावजूद भी प्रधान द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग करते हुए अनुरोध में प्रकरण का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है।

## छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ा

छुटपलपुर। थाना फलेहपुर पुलिस ने सोमवार को नाबालिग बच्चों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भांगपुर पुलिस में गिरफ्तार कर लिया है आरोपी की पहचान विकी उर्फ विकास पुत्र राकेश, निवासी ग्राम मूसल, थाना फलेहपुर के रूप में हुई है पुलिस के अनुसार, आरोपी पर 12 अप्रैल को बांदी की करीब आठ वर्षीय पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप है। इस मामले में थाना हाजाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। थानाध्यक्ष विनय शर्मा के कृशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक बबलू कुमार और डेप्टीसेल ललित कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

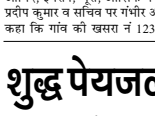
## समीक्षा अधिकारी बनकर लौटे विशेष का स्वागत



सहायपुर। युपीएससी में 37 वीं रैंक हासिल कर समीक्षा अधिकारी बने ग्राम भायला निवासी विशेष प्रजापति का आज नगर आयाम पर जोरदार स्वागत किया गया।

दलीफान एसकचंद स्थित ऋषिपाल प्रोफेशनल के आवास पर विशेष प्रजापति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विशेष का सम्मान करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी ब्रजेश प्रजापति ने कहा विशेष ने सचिव कर दिए कि प्रजापति समाज का युवा किसी से कम नहीं है। मेहनत और लगन हो तो गाँव की भित्ति से निकलकर भी अधिकारी बना जा सकता है। ये उपलब्धि अपने वाली पीढ़ियों को दिशा देगी। विशेष प्रजापति ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपने माता-पिता व पुरुखों के आशीर्वाद को दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने दिन-रात एक कर पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि ये सफलता मेरी अकेले की नहीं है। मेरे माता-पिता का त्याग, शिक्षकों का मार्गदर्शन और पूरे समाज का

## शुद्ध पेयजल पहुंचाना हमारा संकल्प: डा. अजय



शाह टाइम्स ब्यूरो सहायपुर। महापौर डॉ. अजय कुमार ने आज बार्ड 6 वर्षमान कालोनी में आज 1.5 हार्डि पावर के पंप लगाने के कार्य का फंडांचेयर के बीच नारियल फाड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया। कार्यक्रम का आयोजन पार्षद प्रतिनिधि विनोद कुमार सैनी एवं मोहल्ला समिति द्वारा नगर निगम व आईटीसी मिशन सुनहरा क्लब कोर्स के सहयोग से आयोजित किया गया था।

नगर निगम द्वारा लगातार वार्डों में आयोजित किया गया। महापौर डॉ. अजय कुमार ने कहा कि महानगरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति करना निगम का उद्देश्य और संकल्प है। इसके लिए

नगर निगम द्वारा लगातार वार्डों में आयोजित किया गया। महापौर डॉ. अजय कुमार ने कहा कि महानगरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति करना निगम का उद्देश्य और संकल्प है। इसके लिए

## स्वच्छता अभियान में बच्चे बने भागीदार



शाह टाइम्स ब्यूरो सहायपुर। नगर निगम सहायपुर एवं आईटीसी मिशन सुनहरा क्लब अपने स्वच्छता जागरूक अभियान में बच्चों को भी साह्यीदार बना रहा है और उन्हें इस बात के विचार प्रेरित कर रहा है कि वे घर जाकर अपने माता-पिता को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए घर को साफ सफा रखें। नगरायुक्त रिपु निरि के निर्देशन में शहर में स्वच्छता के लिए चलाये जा रहे स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत आज नगर निगम द्वारा उमंग सुनहरा क्लब सेवा समिति के सहयोग से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महामुहुर में बच्चों को प्रेरित किया गया कि अपने माता पिता को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें।

इसके अलावा नगर निगम उमंग सुनहरा क्लब सेवा समिति एवं युवा मोहल्ला समिति द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रीय लोगों के साथ स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर जन जागरूकता बैठक की गयी।





## नहीं थम रही धमकियां

अभी शांति वार्ता को जोकि रविवार को इस्लामाबाद में समाप्त हुई, एक दिन भी नहीं गुजरा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के बंदरगाहों के नाकेबंदी की बात कर डाली। जिसके चलते ईरान का निर्यात विशेष रूप से तेल बाहर नहीं जा सकेगा। जाहिर है अमेरिका अपने इस फैसले से ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। ट्रम्प तो यह भी कह रहे हैं कि उनके इस फैसले में उनके सहयोगी भी साथ हैं। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया ने ट्रम्प के इस बयान के बाद साफ कर दिया कि वह ट्रम्प की इस योजना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं और ईरान की नाकेबंदी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यूं भी नाटो देशों ने ईरान के साथ संघर्ष में अब तक दूरी बनाई हुई है और ब्रिटेन और फ्रांस के नेता तो बराबर ईरान के नेताओं के टच में भी हैं। जाहिर है ट्रम्प की इस नई पहल से खाड़ी में फिर से तनाव बढ़ गया है और जो ट्रम्प की तरफ से ही दो हफ्ते का सीजफायर हुआ था, वह भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प व नेतन्याहू को दुनिया की कोई चिंता नहीं रह गई है। इस युद्ध से लोगों को हो रहे नुकसान से उनका कोई लेना-देना नहीं है। भले ही वह बयान कुछ भी देते रहे हों और लोगों को चिंता की बात करते हों। होना तो यह चाहिए था कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होने के बाद फिर से नए सिरे से बातचीत की को. शिश्न होनी चाहिए थी। अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है। पहले से ही काफी नुकसान हो चुका है और बहुत नुकसान को बचाया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब संघर्षरत लोगों को सद्वृद्धि आएगी, जोकि दूधार्थ से आती दिखाई नहीं दे रही है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि यदि अमेरिका की तरफ से कोई भड़काऊ कार्रवाई होती है तो वह चुप नहीं रहेगा और जवाबी कार्रवाई में देर नहीं लगाएगा। ईरान को संसद के स्पीकर कालिबफ ने अमेरिका को चेताया है कि वह ईरान की नाकेबंदी करने का प्रयास न करें। सवाल तो यह भी है कि जहां अमेरिका यह दावा कर रहा है कि होर्मुज्ज को बंद करने से दुनिया को काफी नुकसान हो रहा है और ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अब सवाल उठता है कि खुद अमे. रिका इस संबंध में क्या कर रहा है। वह भी नाकेबंदी करके दुनिया को संकट में डाल रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों को ही समझना होगा, भले ही संघर्ष उनके बीच हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर सीधे पड़ रहा है। इस समय यह भी देखना बेहद डरावना लग रहा है कि जहां 40 दिन के युद्ध के बाद दोनों पक्षों के रुख में कुछ नमी आनी चाहिए थी, वहाँ और उग्रता दिखाई दे रही है और अब तो रूस और चीन की एंटी भी इसमें होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रम्प ने चीन को सीधे चेतावनी दे डाली है कि अगर वह ईरान को हथियार देता है, तो उस पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा और अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की बात वह कर रहे हैं। चीन ने यह कहकर पलटवार किया है कि होर्मुज्ज तो पहले से ही खुला हुआ था, अमेरिका ने बिना वजह हमला करके इसे बंद कराया है। अभी भी समय है कि परिस्थितियों को और बिगड़ने से बचाया जाए।

## अहम मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही

मौजूदा समय में असली चिंता महिला आरक्षण नहीं, बल्कि प्रस्तावित परिसीमन है, संसद के विशेष सत्र में जिस तरह परिस. मिन का मुद्दा सामने आ रहा है, वह लो. कर्तांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है, सरकार जल्दबाजी में इस विषय को आगे बढ़ा रही है, जिसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा हो सकती है, विपक्ष से समर्थन, तो मांगा जा रहा है, लेकिन इस अहम मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक की मांग को लगातार नजरअंदाज किया गया है, 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिस. मिन जरूरी है। -सोनिया गांधी, अध्यक्ष, काँग्रेस संसदीय दल



भारत की महिलाएं सदैव महान कार्यों में सक्षम रही हैं। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी ने बड़े-बड़े दार्शनिकों को निरुत्तर कर दिया था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ने जिस न्यायपूर्ण तरीके से अपने राज्य का शासन चलाया, उसकी बराबरी उनके समकालीन शासक नहीं कर सकते। रानी लक्ष्मीबाई साहस की एक अमर मिसाल बन गईं। फिर भी, स्वतंत्र भारत जो समानता के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक गणराज्य है ने इन महान महिलाओं की उत्तराधिकारियों को अपनी विधायिकाओं में शायद ही कोई जगह दी। पहली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 4.4 प्रतिशत थी। सात दशक बाद, 17वीं लोकसभा में भी यह आंकड़ा बढ़कर केवल 14.14 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया। व्यक्तिगत प्रतिभा ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन व्यवस्थागत बदलाव अभी भी नहीं आया था। असल में, महिलाएं अपने ही लोकतंत्र में एक तरह से मेहमान बनकर ही रह गईं।

हमारे संविधान ने पहले ही दिन से यह स्वीकार किया था कि जब सदियों से दांचगत विसंगतियां जड़ जमाए बैठी हों, तो केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं होती। संरक्षणत्मक भेदभाव के सिद्धांत के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बाद में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था सफल रही है 24 मार्च 2026 तक, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएं हैं। जिन जगहों पर महिलाएं शासन करती हैं, वहां पानी की आपूर्ति सुचारू होती है, साफ-सफाई की स्थिति बेहतर होती है और लड़कियां स्कूल जाना जारी रखती हैं। इसके बावजूद, संसद में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो विधेयक पेश किए गए थे, वे राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दशकों तक बार-बार निष्प्रभावी होते रहे।

**वह क्षण जिनसे सब कुछ बदल दिया**  
वह अधूरी कड़ी 19 सितंबर 2023 को पूरी हुई। भारत के नए संसद भवन में आयोजित कामकाज के पहले ही सत्र में, शनारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक राजनीतिक दल के सर्वसम्मत समर्थन से पारित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पेश करते हुए दोनों सदनों को बतायारू प्यह कानून केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय महिला की शक्ति, त्याग और

दरअसल यह दलितों को उठाने की नहीं बल्कि गिराने की एक कुटिल चाल है। जो दलित सत्ता के पिछलपुष्प बन राजने. ताओं की इस चाल का हिस्सा बन जाते हैं उनका स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है और दूसरे दलितों के प्रति उनका व्यवहार भी शोषणकारी हो जाता है। जबकि आम दलित का स्वाभिमान अपने पुराने स्तर से भी नीचे गिरा जाता है। इन नारों एवं अभियानों में एक आम दलित के हाथ कुछ नहीं लगता। आंबेडकर ने दलितों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू में मात्र दस वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी।

# आखिरकार सुनी गई आधी आबादी की आवाज



सामर्थ्य के प्रति एक श्रद्धांजलि है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-कोटा भी शामिल है। नए संसद भवन का यह पहला अधि. नियम होना अपने आप में एक घोषणा थीरू अमृत काल के लोकतंत्र की संरचना पूरे भारत के लिए और सभी की भागीदारी के साथ निर्मित की जाएगी। इस अधिनियम में बदलाव लाने की अपार क्षमता है, क्योंकि इसके लागू होने से संसद में महिला सदस्यों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। महिला विधायक निरंतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैंक्यू वही क्षेत्र हैं, जहां भारत में लैंगिक असमानता सबसे अधिक है। एक ऐसी संसद, जिसमें एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, वह अलग तरह के प्रश्न पूछेंगी और अलग तरह के विचार सुनेंगी। इससे भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा, न कि केवल उसकी बाहरी छवि में।

**गरिमा से लोकतंत्र तक की यात्रा**  
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह सप्नशा है

कि जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के बिना राजनी. तिक सशक्तिकरण खोखला होता है। उनके द्वारा शुरू की गई यह यात्रा अत्यंत बुनियादी गरिमा से लेकर सर्वोच्च लोकतांत्रिक भागीदारी तक एक सुविचारित पथ पर आगे बढ़ती है। इसकी शुरुआत एक शौचालय से हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए 10 करोड़ घरेलू शौचालयों ने उन महिलाओं को सुरक्षा और आत्म-सम्मान लौटाया, जिन्हें लंबे समय से इन दोनों से वंचित रखा गया था। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचाया। महिलाओं को मीलों पैदल चलकर पानी ढो कर लाने से मुक्ति मिली जिससे उनका सुबह का कीमती समय जाया हो जाता था। पीएम उज्वला योजना के 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों ने महिलाओं को धुएँ से भरी रसोई से मुक्ति दिलाई। पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर बनाए गए। 55 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले जन धन खातों ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। रघुदाश योजना के ऋण, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, सखी, वन स्टॉप सेंटर और तीन तलाक का

**आधुनिक भारत के लिए एक दृष्टिकोण**  
भारत को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। यह हमारे दौर के सबसे अधिक परिवर्तनकारी संभावित सुधारों में से एक है। महिलाओं के विधाई प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर, यह हर स्तर पर नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा चाहे वे बजट हों जो मातृ स्वास्थ्य के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, वे कानून हों जो पीड़ितों की रक्षा करते हैं, या वे नीतियां हों जो लड़कियों को स्कूल में बनावे रखती हैं और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 तक एक विकसित भारत का दृष्टिकोण इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक तब तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उसके आधे नागरिक उन जगहों से बाहर रहें जहां सत्ता का संचालन होता है। जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा है भारत तभी एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब इसकी महिलाएं न केवल अपने घरों में, बल्कि अपनी संसद में भी पूरी तरह सशक्त होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय महिलाओं के लिए कुछ नया सृजन नहीं करता है।

उन्मूलनरूप प्रत्येक योजना उसी सीढ़ी का अगला पायदान थी, जो उन्हें केवल गुजारा करने की स्थिति से गरिमा की ओर, गरिमा से सामर्थ्य की ओर, और सामर्थ्य से नेतृत्व की ओर निरंतर बढ़ाती गई।

**आधुनिक भारत के लिए एक दृष्टिकोण**  
भारत को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। यह हमारे दौर के सबसे अधिक परिवर्तनकारी संभावित सुधारों में से एक है। महिलाओं के विधाई प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर, यह हर स्तर पर नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा चाहे वे बजट हों जो मातृ स्वास्थ्य के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, वे कानून हों जो पीड़ितों की रक्षा करते हैं, या वे नीतियां हों जो लड़कियों को स्कूल में बनावे रखती हैं और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं।

**आर. विमला, आईएएस**  
(लेखिका महाराष्ट्र सरकार में रैजिस्ट्रार क्विश्नर एवं सचिव पद पर कार्यरत हैं और आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही हैं)

## आंबेडकर को मात्र प्रतीक मत बनाइए



रोहित कौशिक

इस दौर में सभी राजनीतिक दल आंबेडकर पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि सभी राजनीतिक दल महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात् न करके उन्हें मात्र प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं। विडम्बना यह है कि इस दौर में जिस तरह से प्रतीकों की राजनीति हो रही है, उसने महापुरुषों को मात्र मूर्तियों तक ही सीमित कर दिया है। इस नए माहौल में न ही तो राजनीतिक दलों को महापुरुषों के आदर्शों की चिंता है और न ही इन दलों के पीछे चलने वाली भीड़ में महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की हिम्मत है। विडम्बना तो यह है कि जिस दलित वर्ग के उत्थान के लिए आंबेडकर ने अपना सारा जीवन लगा दिया, वह दलित वर्ग भी केवल आंबेडकर की पूजा तक ही सीमित रह गया। न तो दलित नेताओं ने आंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात् कर दलितों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करने की कोशिश की और न ही स्वयं दलित वर्ग

आंबेडकर की मूल चेतना को पकड़ पाया। यही कारण है कि वह धर्म की रूढ़ियों में फंसकर रह गया। दरअसल डॉ. आंबेडकर ने इस सत्य को बहुत पहले ही समझ लिया था कि जब तक दलित वर्ग अपनी शक्ति को पहचान कर सत्ता का भागीदार नहीं बनेगा, उसकी उपेक्षा होती रहेगी। यही कारण था कि उन्होंने दलितों के आरक्षण की वकालत की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौर में सत्ता का भागीदार बने दलित नेताओं को वास्तव में आंबेडकर के विचारों एवं आदर्शों की चिंता है? आज हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए आंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि आज भी आम दलित को शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। यह विडम्बना ही है कि आज राजनी. तिक दल आंबेडकर के नाम का इस्तेमाल अपने उत्थान के लिए कर रहे हैं, न कि दलितोत्थान के लिए। सवाल यह है कि आजादी के बाद राजनेताओं ने आंबेडकर-आंबेडकर चिल्लाने और आंबेडकर के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं का नामकरण करने के अलावा किया ही क्या है? क्या आजादी के बाद हमारे राजनेता आंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात् कर पाए हैं? क्या केवल आंबेडकर के नाम पर पार्क बना देने, उनकी मूर्तियां स्थापित कर देने और उनके विचारों को विचार-गोष्ठियों में दोहरा देने मात्र से ही हम इस दौर में आंबेडकर को प्रार्संगिक बना सकते हैं? शायद नहीं। बड़ी-बड़ी रैलियां आयोजित कर पानी की तरह पैसा बहा देना आंबेडकर का सपना नहीं था। करोड़ों रूपए का

हार पहनकर भव्य पंडाल में दलितों और अपने अनुयायियों लिए महाभोज आयोजित करना भी बाबा साहब की प्राथमिकताओं में नहीं था। क्या ऐसे आयोजनों से वास्तव में दलितों का स्वाभिमान जाग सकता है? शायद स्वादिष्ट भोज का आनंद लेते हुए कुछ समय के लिए उनका स्वाभिमान जाग जाए लेकिन गांव में बैठे हुए उस दलित के स्वाभिमान का क्या होगा जिसे एक जून की रोटी भी नसीब नहीं है। हमारे राजनेता कुछ हजार या लाख लोगों को भव्य भोज देने की अपेक्षा गांव के आखिरी आदमी को दो जून की रोटी देने के बारे में कब सोचेंगे? आंबेडकर ने दलितों के जिस स्वाभिमान की बात की थी वह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित नहीं था। इस दौर में सबसे दुखद यह है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत दलितों के स्वाभिमान को जगाने की बात हो रही है।

आज के राजनेता जब दलितों के साथ खाना खाते हैं और दलितों के घर में ही रात गुजारते हैं तो दलितों का स्वाभिमान जागने लगता है। लेकिन जैसे ही राजनेता अपने महलों में वापस लौटते हैं, दलितों की जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौटने लगती है। अनेक आशवासनों के बाद जब दोबारा दलितों को पुरानी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है तो उन्हें स्वयं महसूस होने लगता है कि यह वोट बैंक का छलावा है। राजनेताओं द्वारा दलितों का स्वाभिमान जगाने की इस खोखली प्रक्रिया से दलित अपना पुराना स्वाभिमान भी खो देते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

# जनसेवा की नई मिसाल देता नेपाल का युवा मंत्रिमंडल

नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया जब 27 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व में बालेन शाह बलेंद्र शाह ने 36 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 15 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया। यह मंत्रिमंडल न सिर्फ नेपाल का सबसे युवा कैबिनेट है, बल्कि दक्षिण एशिया में अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है। इस मंत्रिमंडल के सदस्यों की औसत आयु मात्र 38.21 वर्ष है, दस मंत्री 40 वर्ष से कम उम्र के, पांच महिला मंत्री और 80 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के पास स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री। यह आंकड़े नेपाल की राजनीति के पारंपरिक चेहरे को पूरी तरह बदल रहे हैं।

यह कैबिनेट जेन-जी आंदोलन के परिणामस्वरूप सत्ता में आई है। भ्रष्टाचार, पुरानी पार्टियों की नाकामी और युवाओं की मांगों को लेकर हुए आंदोलन ने आरएसपी को भारी बहुमत दिलाया। अब यह युवा टीम न सिर्फ नेपाल में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दुनिया का सबसे युवा कैबिनेट और सबसे शिक्षित मंत्रिमंडल के रूप में प्रसिद्ध हो रही है। कई भारतीय अखबारों ने इसे जनरेशनल शिफ्ट करार दिया है। विश्व स्तर पर इसकी सराहना हो रही है, क्योंकि यह पारंपरिक राजनीति से हटकर योग्यता, तकनीकी विशेषज्ञता और समावेशिता पर आधारित है। यह दक्षिण एशिया का चमकता उदाहरण है, जहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के कैबिनेट अक्सर वरिष्ठ नेताओं पर निर्भर रहते हैं।

इस कैबिनेट की सबसे बड़ी ताकत इसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। प्रधानमंत्री बालेन शाह स्वयं सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक पूर्वाचल विश्वविद्यालय और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एम.टेक (निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंगलूरु, भारत) हैं। वे काठमांडू के पूर्व मेयर और लोकप्रिय रेपर भी हैं। उनकी टीम में दो डॉक्टरेट धारक और दस स्नातकोत्तर सदस्य हैं। वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले (41 वर्ष, कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ) अर्थशास्त्र में पीएचडी (ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी), हार्वर्ड से एमपीए/आईडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक हैं। वे पूर्व में यूएनडीपी के एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक सलाहकार और नेपाल की राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता आर्थिक सुधार, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल (47 वर्ष) अमेरिका के विस्कॉन्सिन-मैडिसन से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट से पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्नातक हैं। वे टीच फॉर नेपाल के सह-संस्थापक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार का प्रमुख अभियान है।

शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा युवा एवं खेल मंत्री सस्मित पोखरेल (29 वर्ष) कैबिनेट के सबसे युवा सदस्य हैं। वे काठमांडू विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट एवं कानून में स्नातक हैं और पॉलिसी, गवर्नेंस एवं भ्रष्टाचार-निरोध पर मास्टर्स कर रहे हैं। वे बालेन के मेयर काल में शहरी नियोजन सलाहकार रह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता (38 वर्ष) भारत के

ग्वालियर से नर्सिंग में मास्टर्स और दिल्ली के एम्स से प्रशिक्षित हैं। सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल (32 वर्ष) एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म (चेन्नई) से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा रखती हैं। श्रम मंत्री दीपक कुमार साह (34 वर्ष) लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से पीएचडी स्कॉलर, एलएएसई से हेल्थ पॉलिसी में मास्टर्स और आईओएम से पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स रखते हैं।

महिला, बाल-बालिका एवं जर्ष्ण नागरिक मंत्री सीता बादी (30 वर्ष) राजनीति विज्ञान में मास्टर्स हैं और बादी समुदाय की प्रतिनिधि के रूप में समावेशिता का प्रतीक हैं। कानून मंत्री सोबिता गौतम (30 वर्ष) राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय से बीए एलएलबी हैं और संसदीय समितियों में सक्रिय रहती हैं। भौतिक पूर्वाधार मंत्री सुनील लाम्मल (35 वर्ष) भी भारत से एमटेक (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) हैं।

गौरतलब है कि यह योग्यताएं महज डिग्रियां नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव से जुड़ी हैं। यूएनडीपी, टीच फॉर नेपाल, आपदा राहत संगठन रहामो नेपाल और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में इन सभी की अहम भूमिका रही है। पांच महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी जैसे सीता बादी समावेशिता को मजबूत करती है। देखा जाए तो नेपाल का यह कैबिनेट अपने पड़ोसियों से अलग दिखता है। भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 सदस्य हैं, जिसमें 57 सदस्य स्नातक या उससे ऊपर हैं, लेकिन 11 सदस्य मात्र 12वीं पास हैं। कई मंत्री राजनी. तिक अनुभव पर निर्भर हैं, जबकि युवा चेहरे कम हैं।

वहीं चीन का मंत्रिमंडल अत्यधिक शिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र से भरा है, लेकिन उनकी औसत आयु 55-60 वर्ष के आसपास है और निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत पार्टी संरचना पर आधारित है। बांग्लादेश के हालिया कैबिनेट में 46/50 सदस्य उच्च शिक्षा वाले हैं तीन पीएचडी, लेकिन वहां भी वरिष्ठता और राजनीतिक वफादारी प्रमुख है।

नेपाल का कैबिनेट इन सभी से युवा, अधिक समावेशी और योग्यता-आधारित है। भारत और चीन की तुलना में यहां भ्रष्टाचार-विरोधी (डिलीवरी बेस्ड गवर्नेंस) पर जोर है, जो पड़ोसियों में अक्सर कम देखा जाता है। हालांकि, कुछ विश्लेषक चेताते हैं कि इस मंत्रिमंडल के पास अनुभव की कमी एक चुनौती है। भारत की तरह बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था या चीन की तरह दीर्घकालिक नियोजन यहां अभी संभव नहीं, लेकिन पारदर्शिता और तेज निर्णय लेने की क्षमता नेपाल को लाभ दे सकती है। केवल दो सप्ताह पुरानी यह सरकार पहले ही 100 सूत्री शासन सुधार एजेंडा लागू कर चुकी है। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रालयों का पुनर्गठन, दक्षिण एशिया संघर्ष के प्रभाव से नेपाली प्रवासियों की सुरक्षा, 'कार्का आयोग' रिपोर्ट पर कार्रवाई और सर्वविध संशोधन पर चर्चा पत्र तैयार करने जैसे कदम उठाए गए। शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने पार्टी-आधारित छात्र संगठनों को समाप्त करने और स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने निजी अस्पतालों में 10 प्रतिशत मुफ्त बेड सुनिश्चित करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले आर्थिक स्थिरता, पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचे पर ध्यान



विनीत नारायण

दे रहे हैं। श्रम और स्वास्थ्य मंत्रियों की स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञता गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में मदद करेगी। विदेश मंत्री शिशिर खनाल की पॉलिसी विशेषज्ञता नेपाल की कूटनीति को मजबूत करेगी। युवा बेरोजगारी घटाने, शिक्षा गुणवत्ता सुधारने, स्वास्थ्य पहुंच बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास पहले ही दिख रहे हैं। दैनिक प्रगति निगरानी प्रणाली लागू कर सरकार जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है। हालांकि, चुनौतियां यहां भी हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में पहुंच, संसाधन सीमाएं और पुरानी पार्टियों का विरोध। फिर भी, यह कैबिनेट जनता की उम्मीदें पूरी करने की राह पर है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो नेपाल का यह 'जेन-जी' कैबिनेट न सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए मिसाल है, बल्कि विकासशील देशों को सिखाता है कि योग्यता और युवा ऊर्जा राजनीति को बदल सकती है। यदि यह टीम अपने 100 सूत्री एजेंडा को ईमानदारी से लागू कर पाई, तो नेपाल आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और सुशासन का नया मॉडल बन सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

# ब्रिटेन होर्मुज की नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा

ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने कहा: ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली किसी भी कार्रवाई को समर्थन नहीं देंगे

लंदन/अंकारा/कैनबरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनका देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली किसी भी नौसैनिक नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिटेन को ईरान के साथ युद्ध में नहीं घसीटा जाएगा। स्टार्मर ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को नौवहन के लिए पूरी तरह खुला रखना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं और लोगों के लिए बिजली-गैस के बिल बढ़ रहे हैं।



■ अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य को नाकेबंदी में सहयोग के लिए अनुरोध नहीं किया: आस्ट्रेलिया हम चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे और फिर से शुरू हो हम इस संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं: अल्बानीज

## रणनीतिक जल क्षेत्र या तो सबके लिए सुरक्षित होंगे या किसी के लिए भी नहीं: ईरान

तेहरान। ईरान के सशस्त्र बलों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, तो क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को 'समुद्री डकैती' करार देते हुए कहा कि ए रणनीतिक जल क्षेत्र 'या तो सबके लिए सुरक्षित होंगे या किसी के लिए भी नहीं।' इस बीच, तुर्की के विदेश

मंत्री हाकान फिदान ने उम्मीद जताई कि होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा निकट भविष्य में कूटनीतिक रास्तों से सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि इसके विनियमन (रेगुलेशन) में कुछ बदलाव संभव हैं। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा युद्धविराम को 45 से 60 दिनों के लिए बढ़ाने का सुझाव भी दिया।

चाहिए। अल्बानीज ने कहा कि आस्ट्रेलिया वैश्विक ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्रीय तनाव के समाधान के लिए वार्ता

फिर से शुरू होनी चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी केंद्रीय कमान ने घोषणा की है कि वह ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले समुद्री यातायात को नाकेबंदी शुरू करेगा। अल्बानीज ने

## जापान ने होर्मुज में माइनस्वीपर तैनाती का फैसला टाला

टोक्यो। समुद्र के नीचे बिछे बारूद को साफ कराने के लिए तैयार दिख रही जापान सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जापान ने माइनस्वीपर भेजने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिनोरु किहारा ने कहा कि जापान ने अभी तक होर्मुज स्ट्रेट में माइन-स्वीपिंग अभियान के लिए अपने समुद्री आत्मरक्षा बल (मेरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स, यानी जेएमएसडीएफ) को तैनात करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आगे का फैसला स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। किहारा ने मीडिया को बताया कि जापान दोनों पक्षों के बीच एक पूरी समझ की दिशा में आगे बढ़ने की अपील कर रहा है।

कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे और फिर से शुरू हो। हम इस संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य सभी के लिए खुला रहे। हम यह भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहे। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री 14 से 17 अप्रैल के बीच ब्रुनेई और मलेशिया की यात्रा करेंगे, जहां ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर चर्चा होगी। यह यात्रा ऊर्जा, उर्वरक और अन्य जरूरी सामानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग करने के आस्ट्रेलिया के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। अल्बानीज ब्रुनेई में सुलतान हाजी हसनल बोल्कियाह से मिलकर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और जरूरी चीजों के व्यापार पर चर्चा करेंगे। ब्रुनेई आस्ट्रेलिया के डीजल आयात का नौ प्रतिशत और फर्टिलाइजर-ग्रेड जबकि आस्ट्रेलिया ब्रुनेई को खाद्य और कृषि उत्पादों का एक अहम सप्लायर बना हुआ है। वह मलेशिया में ईंधन की आपूर्ति और अन्य जरूरी सामानों पर चर्चा करने के लिए दावा सेरी अवक बिन इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। मलेशिया, आस्ट्रेलिया के लिए रिफाईंड ईंधन का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है और उर्वरक-ग्रेड यूरिया के आयात का 10 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आता है। विदेश मंत्री, सोनेट पेनी वॉंग, इन यात्राओं के दौरान अल्बानीज के साथ रहेंगे। इस बीच, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने नाकेबंदी की चेतावनी को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी जल्द ही मौजूदा ईंधन कीमतों को याद करेंगे।

# रूस ले जाएगा ईरान का यूरेनियम!

मास्को। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। इस बीच रूस ने भविष्य में होने वाली शांति वार्ता के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। क्रैमलिन ने सोमवार को जानकारी दी कि रूस अमेरिका के साथ किसी भी संभावित शांति समझौते के तहत ईरान का संवर्धित यूरेनियम (enriched uranium) अपने पास रखने के लिए तैयार है।



■ होर्मुज तनाव के बीच पुतिन का बड़ा दांव शांतिवार्ता के लिए पेश की ये योजना

बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच पिछले हफ्ते हुई बातचीत नाकाम रही। इससे युद्ध को तुरंत खत्म करने की उम्मीद टूट गई है। फरवरी के आखिर में शुरू हुए इस युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी संकट में है। रूस के पास दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है। उसने शांति समझौते के लिए कई बार ईरान का यूरेनियम अपने यहां रखने की पेशकश की है। क्रैमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने यह प्रस्ताव अमेरिका और क्षेत्र के अन्य देशों के सामने रखा था। उन्होंने साफ किया कि यह प्रस्ताव आज भी लागू है, लेकिन अब तक किसी ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। इसी बातचीत के दौरान क्रैमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी को कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य की घेराबंदी करने की बात कही थी। यह जलमार्ग व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल ने जब से ईरान पर हमले शुरू किए हैं, तब से यह रास्ता पूरी तरह टप पड़ा है।

## ईरान को नई शर्तों व प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा



■ सहमति के बहुत करीब होने के बावजूद बदलती शर्तों और प्रतिबंधों को हमारे समक्ष लाया गया: अराघची

नई दिल्ली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस्लामाबाद वार्ता को विफलता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि 'बदलती शर्तों और प्रतिबंधों' को हमारे सामने रखा गया। अराघची ने सोमवार को 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा कि वार्ता के दौरान सहमति के बहुत करीब होने के बावजूद बदलती शर्तों और प्रतिबंधों को हमारे समक्ष लाया गया। अराघची ने एक अन्य

पोस्ट में कहा कि कोई सबक नहीं सीखा गया। सद्भावना से सद्भावना पैदा होती है और शत्रुता से शत्रुता। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि 47 वर्षों में उच्चतम स्तर की गंभीर वार्ता में, ईरान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए नैक नीयत के साथ अमेरिका के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि लेकिन जब हम 'इस्लामाबाद सहमति पत्र' से केवल कुछ ही दूर थे, तो हमें बदलती शर्तों और प्रतिबंधों सामना करना पड़ा।

## ईरान में अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना: ट्रंप ने पोप पर साधा निशाना

न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो चतुर्थ के विरुद्ध प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे धर्मगुरु की आवश्यकता नहीं है जो उनकी नीतियों का विरोध करते हों। पोप ने ईरान में अमेरिका के कदमों की आलोचना की है। विशेष रूप से, उन्होंने ईरानी लोगों के विरुद्ध अमेरिकी धर्मकर्मियों को अस्वीकार्य बताया। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने सैन्य कर्मियों के लिए प्रार्थना के आह्वान किया था, जिसके बाद पोप ने एक प्रवचन में कहा था कि प्रभुत्व जमाने की इच्छा मसीह के मार्ग के अनुरूप नहीं है। अमेरिकी नेता ने 'दुष्ट सोशल' पर कहा कि मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जिसे लगता हो कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जिसे अमेरिका का वनेयुल्ला पर हमला करना भयानक लगता हो।

## हिजबुल्लाह लेबनान-इजरायल के बीच वार्ता का विरोधी

लेबनान और इजरायली दुश्मन के बीच सीधी बातचीत को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं: कीमती

बेरुत। हिजबुल्ला का राजनीतिक परिषद के उपाध्यक्ष महमूद कोमती ने कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान और इजरायल के बीच सीधी बातचीत का विरोध करता है और उसे इससे किसी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं है। कोमती ने रूसी समाचार एजेंसी 'स्पुतनिक' से कहा कि लेबनान में संघर्षविराम ईरान की वजह से हुआ है।



■ कहा: लेबनान सरकार का हिजबुल्लाह के खिलाफ रुख देश में आंतरिक विभाजन पैदा कर सकता है

हमें लेबनान के संघर्ष में वार्ता से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं है। हम लेबनान और इजरायली दुश्मन के बीच सीधी बातचीत को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह के नेतृत्व के अनुसार, ईरान के कड़े रुख ने ही अमेरिका और इजरायल को लेबनान में संघर्षविराम वार्ता के लिए सहमत होने पर मजबूर किया। इस बीच, अमेरिका और इजरायल को इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वे इन वार्ताओं के सूत्रधार हों। कोमती ने बताया कि इस दिशा में दबाव इन तथ्यों से उभरा है कि इजरायल ने तो लेबनान और न ही लेबनानी देश को मान्यता देता है और अचानक आज, इजरायल लेबनान

वार्ता मंगलवार को होगी। अमेरिका ने लेबनान को गारंटी दी है कि बातचीत शुरू होने से पहले इजरायल बेरुत पर बमबारी नहीं करेगा। महमूद कोमती ने यह भी कहा कि लेबनान सरकार का हिजबुल्लाह के खिलाफ रुख देश में आंतरिक विभाजन पैदा कर सकता है और देश को अराजक कता में धकेल सकता है। कोमती ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि इजरायल के खिलाफ लड़ाई में समूह का समर्थन करने वाली जनता के दबाव से सरकार भी बदल सकती है। उन्होंने कहा कि आज हम स्वतंत्रतापूर्ण विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं जो जनमत को व्यक्त करते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार अपनी नीतियों और अपने रुख के कारण खूद को एक गंभीर मुश्किल में धकेल देगी, जिससे उसका पतन हो जाएगा। जब कोमती से पूछा गया कि क्या जनता का आक्रोश लेबनान में सरकार बदलने के उद्देश्य से व्यापक विरोध प्रदर्शनों का रूप ले सकता है, तो उन्होंने उल्लेख किया कि 'सभी विकल्प संभव हैं।' प्रवक्ता के अनुसार, समस्या यह है कि सरकार हिजबुल्लाह और प्रतिरोध का सम्मान नहीं कर रही है।

## हिजबुल्लाह को मध्य पूर्व संघर्ष के समाधान में रूस की भूमिका की है उम्मीद

बेरुत। हिजबुल्लाह के राजनीतिक परिषद के उपध्यक्ष महमूद कोमती ने बताया कि हिजबुल्लाह को उम्मीद है कि रूस, जिसके इरान सहित मध्य पूर्वी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इस क्षेत्र में संघर्ष के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोमती ने कहा कि आज, रूस, ईरान के साथ अपने संबंधों और क्षेत्रीय स्तर पर कई अरब देशों और लेबनान के साथ अपने निष्ठापूर्ण संबंधों के कारण, एक भूमिका निभा सकता है और हम इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व रूप से (राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप, ईरान को प्रभावित करने और युद्धविराम हासिल करने के लिए रूस की ओर रुख कर रहे हैं।



गिरापुर। दिवंगत दिग्गज पादर गाविका आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित करती छात्राएं।

## अमेरिका में यू वीजा के लिए धोखाधड़ी के आरोप में 10 भारतीय नागरिक दोगी

बोस्टन। अमेरिका के बोस्टन में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने 10 भारतीय नागरिकों को सुविधा स्टोरों में फर्जी सशस्त्र डकैती के मामले में दोगी ठहराया है। इन डकैतियों का मकसद स्टोर क्लकों को आब्रजन आवेदनों में पीड़ित के रूप में फर्जी दावा करने की अनुमति दिलाना था। आरोपियों पर मार्च 2026 में आरोप लगाए गए थे। अभियोग पत्र में प्रत्येक

प्रतिवादी पर वीजा धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है जिसके लिए अधिकतम पांच साल की जेल, तीन साल की गिरफ्तारी में रिहाई और 250000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है। मैसाचुसेट्स स्थित अर्दोनी कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, सजा पूरी होने के बाद सभी को देश से निकाला जा सकता है।

## सुरक्षा परिषद में रूस व चीन के प्रस्ताव पर जमीनी स्थिति के अनुसार चर्चा होगी: रूस

मास्को। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए रूस और चीन की ओर से प्रस्तावित संकल्प पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मतदान की तारीख वहां की जमीनी स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इससे पहले, रूस और चीन ने प्रस्ताव दिया था कि सुरक्षा परिषद पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति पर एक वैकल्पिक मसौदा प्रस्ताव पर विचार करे, जिसमें समुद्री सुरक्षा के पहलुओं को भी शामिल किया जाए। रूस के विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभाग के निदेशक किरिल लोकोनोव ने स्पष्टता से कहा कि बैठक में हमने अपने चीन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के पक्ष में एक वैकल्पिक मसौदा प्रस्ताव की घोषणा की है। इस पर मतदान की तिथि जमीनी हालात को देखते हुए निर्धारित की जाएगी।

## रूस ने की ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की आलोचना

पश्चिम एशिया की स्थिति अब भी अस्थिर है और संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है

मास्को। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे वैश्विक बाजारों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। क्रैमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित करती रहेगी और इसके आर्थिक परिणाम दीर्घकालिक हो सकते हैं।



हुई है, लेकिन ये दावे पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सामने आए हैं। इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत कर कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं पर जोर दिया है। राष्ट्रपति के सहयोगी निकोलाई पत्रुशोव ने नाटो पर 'सी शील्ड 2026' अभ्यास के जरिए काला सागर क्षेत्र में सैन्य ढांचे का विस्तार करने के आरोप लगाया है। पत्रुशोव ने कहा कि रूस का मुकाबला करने के उद्देश्य से किए जा रहे इन युद्धाभ्यासों के लिए रोमानिया को मुख्य आधार के तौर पर चुना गया है जो नाटो की क्षेत्रीय स्थिति को लेकर रूस की बढ़ती चिंता का संकेत है। पुतिन ने मास्को में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो के साथ बातचीत के दौरान, विश्वास व्यक्त किया कि हालिया उत्तर-चढ़ावों के बावजूद दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को स्थिर करने और उसका विस्तार करने में सक्षम होंगे। वहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो के साथ बैठक में पुतिन ने ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृषि और फार्मा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही।

पश्चिम एशिया की स्थिति अब भी अस्थिर है और संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है

## पाकिस्तान को 46500 करोड़ की मदद देंगे सऊदी-कतर

इससे यूएई का 29000 करोड़ कर्ज चुकाएगा, पैसे लौटाने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर से 5 अरब डॉलर (लगभग 46500 करोड़ रुपये) की वित्तीय मदद मिलेगी। यह मदद ऐसे समय में आ रही है, जब देश को इस महाने के अंत तक यूएई को 3.5 अरब डॉलर (लगभग 29000 करोड़ रुपये) चुकाने हैं। डान की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की कमजोर विदेशी मुद्रा स्थिति संभालने के लिए यह मदद अहम मानी जा रही है। यूएई ने हाल ही में कर्ज रोलओवर की नीति में बदलाव किए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रैल तक यूएई का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने का फैसला किया। तब शेंडयूल के मुताबिक 23 अप्रैल तक पाकिस्तान को इस कर्ज की आखरी किस्त देनी है। इसका मतलब कर्ज चुकाने के लिए



सिर्फ 11 दिन का समय बाकी है। इसके अलावा, अप्रैल में पाकिस्तान को कुल करीब 4.8 अरब डॉलर चुकाने हैं, जिसमें एक बड़ा बान्ड भी शामिल है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए 3 साल का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत उसे करीब 7 अरब डॉलर की मदद मिलेगी। इसके बदले आईएमएफ ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान के बड़े कर्जदाता सऊदी

अरब, चीन और यूएई अपने कर्ज के पैसे 3 साल तक तक पाकिस्तान में ही रखेंगे, यानी वे पैसे वापस नहीं निकालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगे चलकर कतर, यूएई की जगह ले सकता है। यूएई ने हाल में कर्ज रोलओवर की नीति बदलकर सऊदी-उम्र एक्सटेंशन शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान पर जल्दी भुगतान का दबाव बढ़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने यूएई को 3.5 अरब डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपये का कर्ज 11, 17 और 23 अप्रैल को अलग-अलग किस्तों में लौटाने का फैसला किया। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा पहले ही दूसरे देशों की मदद पर टिका है। कर्ज पाकिस्तान को अलग-अलग समय पर मिला था। यूएई ने 2018 में 2 अरब डॉलर का लोन दिया था, जिसे बार-बार बढ़ाया गया। 2023 में 1 अरब डॉलर और दिया गया था, ताकि पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तें पूरी कर सके। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच साझेदारी काफी समय से चल रही है। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब ने इस्लामाबाद में सऊदी के वित्त मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-जादान से मुलाकात की थी।

## ट्रंप-पुतिन के समर्थन के बावजूद हंगरी में चुनाव हारे आर्बन

बुडापेस्ट। विकटर आर्बन हंगरी का प्रधानमंत्री चुनाव हार गए हैं। वे 16 साल से सत्ता में थे। विपक्षी तित्स्जा पार्टी के पीटर मग्यार अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मग्यार पहले आर्बन की पार्टी फिदेस से जुड़े थे, लेकिन पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनसे अलग हो गए थे। आर्बन दुनिया के गिने-चुने नेताओं में हैं, जिनकी करीबी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याह से हैं। इस बार के चुनाव में करीब 80 प्रतिशत रिर्कांड वोटिंग हुई थी। नतीजों को बड़े राजनीतिक उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। इसका असर यूरोप और

**यौन समस्याएं**

(यौन समस्याओं के विशेषज्ञ)

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

**डा. सम्राट**

नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन केफ्यूल अफीम, चरस, डोडे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

**नावल्टी सिनेमा चौक**  
मुजफ्फरनगर (यूपी.)

**M-9412211108**